भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 999

दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- एग्रीस्टैक परियोजना

999. श्री रितेश पाण्डेय:

श्री जयदेव गल्ला:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च स्तरीय कार्यबल द्वारा इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए) रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने, देश में एग्रीस्टैक के सृजन/कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित रूपरेखा और एग्रीस्टैक के विकास की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार एग्रीस्टैक के प्रभावी विकास के लिए हितधारकों से परामर्श ले रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एग्रीस्टैक की स्थापना के लिए निजी कंपनियों के साथ करार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एग्रीस्टैक के अंतर्गत बनाए जाने वाले समेकित डाटाबेसों तक राज्यों को पहुंच प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनियों के साथ डेटा साझा करने का कोई तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गोपनीयता और डेटा दोहन के संभावित खतरे के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(च) सरकार ने एग्रीस्टैक के लिए अवधारणाओं के प्रमाण (पीओसी) विकसित करने के लिए कितनी प्रौद्योगिकी/स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): विभाग ने देश में एग्रीस्टैक बनाने का काम शुरू कर दिया है। एग्रीस्टैक बनाने के लिए विभाग ने "इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए)" की मूल अवधारणा को अंतिम रूप दिया है जो एग्रीस्टैक के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इसके लिए, एक कार्य बल का गठन किया गया और आगे चलकर आईडीईए पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया और

विषय विशेषज्ञों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा आम जनता से उनकी टिप्पणियां मांगी गईं।

(ग): जी नहीं।

(घ): एग्रीस्टैक एक संघबद्ध संरचना है और डेटा का स्वामित्व केवल राज्यों के पास ही होता है।

(ड.): केवल सरकार ही किसानों का संघबद्ध डेटाबेस देख सकती है। किसानों के संघबद्ध डेटाबेस तैयार करने में कोई निजी कंपनी शामिल नहीं है। अब तक, विभाग में मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और सरकार में विभिन्न डेटा साइलो से डेटा लेकर एक संघबद्ध डेटाबेस बनाया जा रहा है।

(च): डेटाबेस उपयोग के मामलों के विकासार्थ विभिन्न कंपनियों के साथ अवधारणाओं के प्रमाण (पीओसी) के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तदनुसार कार्यान्वित किए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/करारों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.999
अनुबंध

प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकसित करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी/एग्री-टेक/स्टार्टअप कंपनियों के साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन का विवरण:

क्रम सं	कंपनी का नाम	ध्यानाकर्षण क्षेत्र
1	माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	100 गांवों में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किसान को सशक्त बनाने के लिए मूल्य श्रृंखला (खेत से कांटे तक) में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु।
2	ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	"नेशनल एग्रीकल्चर जिओ हब" की स्थापना एवं लॉन्च के लिए तथा किसानों के डेटाबेस पर जीआईएस परत को सक्षम करने के लिए उनके 'आर्कजीआईएस' प्लेटफॉर्म का उपयोग करने हेतु।
3	अमेज़न वेब सर्विसेज इंडिया	कृषि मूल्य श्रृंखला में डिजिटल सेवाओं के लिए और डिजिटल कृषि के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए
4	स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के लिए कृषि विभाग के साथ सहयोग करने हेतु
5	पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान प्राइवेट लिमिटेड	कृषि प्रबंधन और किसान सेवा के लिए
6	जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड	पहले चरण में प्राथमिक हस्तक्षेप मॉड्यूल, अर्थात परामर्शी (बुनियादी और साथ ही उन्नत) सेवा शुरू करने के लिए
7	आईटीसी लिमिटेड	एक अनुकूलित 'साइट विशिष्ट फसल परामर्श ' सेवा के शुरू करने और डेयरी मूल्य श्रृंखला के डिजिटलीकरण तथा गेहूं की फसल के प्रचालन में सहायताकरने के लिए
8	सिस्को कॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	किसानों, प्रशासन, शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करने में अवधारणा के प्रमाण की अवधारणा के लिए
9	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)	किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए एक डिजिटल मंडी हेतु
10	निंजाकार्ट- 63आइडियाज इंफोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड	एग्री मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के विकास और मेजबानी के लिए
11	राष्ट्रीय उद्यमिता नेटवर्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट (वाधवानी एआई)	2022 खरीफ मौसम में लगभग 50,000 अग्रणी किसानों और 500000+ कैस्केड किसानों तक कपास किसानों के लिए कीट प्रबंधन समाधान को बढ़ाना। एआई/एमएल समाधान करना।

****